अब पीएनजी कनेक्शन के लिए टारगेट

आवेदन और कनेक्शन की लगातार होगी मॉनीटरिंग

संकट के बीच एलपीजी के विकल्प पर दिया जोर

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. राज्य सरकार किल्लत के बीच अब सीएनजी के विकल्पों पर जोर दे रही है. लिहाजा अब प्रदेश में पीएनजी कनेक्शन के लिए नए टारगेट दिए जा रहे हैं.

शनिवार को अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सीजीडी संस्थाओं, ऑयल कम्पनी एवं जिला आपूर्ति अधिकारियों की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाएं अगले 3 माह में दिये जाने वाले पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित करें. साथ ही सीजीडी संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे आवेदन एवं उसके विरुद्ध दिये जा रहे पीएनजी कनेक्शन की सतत मॉनीटरिंग की जाये. एसीएस श्रीमती शमी ने सीजीडी संस्थाओं को पीएनजी के लाभ एवं पीएनजी कनेक्शन की प्रक्रिया से संबंधित एफएक्यू तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश नोडल सीजीडी संस्था थिंक गैस को दिये. भारत सरकार के गतिशक्ति पोर्टल पर सीजीडी संस्थाओं को पाइप-लाइन अपलोड करने के निर्देश दिये गये. सीजीडी संस्थाएं जिलेवार एवं लोकेलिटीवाइज कैम्प शेड्यूल कर जिला प्रशासन एवं विभाग को उपलब्ध करायें. शहर के जिन स्थानों में पाइप-लाइन गई है, उसके आस-पास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ऑयल कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि वह पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिये तत्काल आवेदन करें. इसके बाद पीएनजी कनेक्शन प्राप्त न करने की स्थिति में आगामी 3 माह में एलपीजी का कनेक्शन बंद किया जा सकता है. जिला आपूर्ति अधिकारियों को एमपीआईडीसी के जिला अधिकारी, जिले में स्थित पॉलीटेक्निक तथा आईटीआई से प्रशिक्षणार्थियों की सूची सीजीडी संस्था को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये. सीजीडी संस्था द्वारा इन प्रशिक्षणार्थियों को वर्तमान वेण्डर के साथ क्लब कर मैन पॉवर बढ़ाया जाएगा. एसीएस श्रीमती शमी ने कहा कि एलपीजी बुकिंग करने के बाद कितने दिन में डिलेवरी होगी, इस संबंध में उपभोक्ताओं को एसएमएस भेजना सुनिश्चित करें. प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है.

पीएनजी कनेक्शन विस्तार पर जोर

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रदेश में कार्यरत 10 संस्थाओं को पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की मांग और शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है. पीएनजी पाइप लाइन जिन क्षेत्रों में बिछ चुकी है, वहां आवासीय परिसर, स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज, कम्युनिटी किचन और आंगनवाड़ी केंद्रों को आवेदन प्राप्त होने के 5 दिन में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

मंत्रालय के गलियारे से

कन्हैया लोधी

विभाग बदला, फिर भी मनमानी नहीं रूकी

प्रदेश के एक ताकतवर अफसर का कुछ समय पहले विभाग बदल दिया गया था. जिस विभाग को बदला गया, वहां के ताकतवर कॉडर के साथ साहब तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, इसे लेकर लगातार शिकवा- शिकायत का दौर चल रहा था.

यहां तक कि विभाग के मुखिया कई मामलों में स्वयं को असहाय महसूस करते थे, आखिरकार पूरे कॉडर की मुहिम रंग लाई और उन्हें विभाग से रूखसत होना पड़ा, लेकिन दूसरी जगह पहुंचने के बाद भी लगता है साहब के मिजाज में कोई बदलाव नहीं आया, साहब के साथ एक विभाग पिछले कार्यकाल में भी चिपका हुआ था और इस बार भी चिपका रह गया है, अब इसी विभाग से जुड़े एक ताकतवर संवैधानिक संस्था के फरमान को साहब ने धता बता दिया है और साफ इंकार कर दिया है. इससे अब अघोषित द्वंद की स्थिति बन गई है. साहब का मिजाज तो मिजाज ही है, विभाग बदल गया, लेकिन मनमानी नहीं रूक रही है.

क्या अब भाग्योदय का समय आ गया

पिछले विधानसभा चुनाव में खेत रहे एक ताकतवर नेता के लगता है कि अब भाग्योदय का समय आ गया है. अब सब कुछ उनके पक्ष में होता दिख रहा है. परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि एक बार फिर विधानसभा की राह उनके लिए खुल सकती है. पिछले कार्यकाल तक सरकार की आंख, कान, नाक रहे ये नेताजी लंबे समय से गर्दिश में रहे, अब ताजा जानकारी के मुताबिक उपचुनाव की तैयारियों में लग गए हैं. यदि कोई और पेंच नहीं आया तो फिर उनके क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है. अब देखना ये है कि आधी बाजी तो उन्होंने मार ली है, तो क्या पूरी भी मार पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

फजीहत कराने का आइडिया दिया किसने

पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश मुखिया ने अति आत्मविश्वास दिखाया, जिसका खामियाजा उन्हें तुरंत ही भुगतना पड़ गया. दरअसल नेता अपने आस-पास बने बबल में ऐसे घिरे रहते हैं, कि उन्हें जमीनी सच्चाई की ज्यादा भनक नहीं होती. लिहाजा साहब ने भी रेंडमली अपने नेतृत्व का रेफरेंडम करा लिया, उन्हें भरोसा था कि सब एक सुर में उनके लिए कसीदें पढ़ेंगे, लेकिन ये दांव उलटा पड़ गया. उनके निर्णयों को भी खुले में चुनौती मिल गई. बस फिर क्या था, जितना रायता उन्होंने फैलाया, बाकी वक्त उन्होंने इसे समेटने में ही लगा दिया. अब लोग ये तलाशने में लगे हैं कि आखिर उन्हें अपनी फजीहत कराने का आइडिया दिया किसने था.

संगठन पर सरकार का असर

लगता है कि भाजपा संगठन पर अब सरकार का असर होने लगा है. अब तक तो प्रशासनिक तबादले ही देर रात को होते थे, लेकिन अब राजनीतिक नियुक्तियां भी देर रात होने लगी है. पिछले दिनों भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई. ये सूची दिन में भी किसी समय जारी हो सकती थी, यदि देर रात को सूची को अंतिम रूप दिया गया तो भी अगले दिन तक का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन सूची मध्य रात्रि को जारी की गई. यानी अब प्रशासन के साथ राजनीति में भी चौंकाने वाले निर्णय कभी भी किसी भी समय हो सकते हैं, भले ही देर रात क्यों न हो?

एनएसयूआई का पोस्टर प्रदर्शन

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने भोपाल में कथित फर्जी अस्पतालों के बढ़ते मामलों के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया.

संगठन ने पोस्टर अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो इन अवैध अस्पतालों को संरक्षण दे रहे हैं. एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने आरोप लगाया कि शहर में कई अस्पताल नियमों का उल्लंघन करते हुए कागजों में फर्जी तरीके से डॉक्टरों और स्टाफ का उल्लेख कर संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतों और विरोध के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है. प्रदर्शन के दौरान लगाए गए पोस्टरों में व्यंग्यात्मक संदेश लिखे गए, जैसे 'भोपाल में फर्जी अस्पताल खोलने के लिए संपर्क करें नट्टू शर्मा' और 'फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट के लिए संपर्क करें टीम नटवरलाल'.

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाए विभाग : संजय

सेमिनार में 44वें उप पुलिस अधीक्षक बैच के अधिकारियों ने लिया भाग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी भोपाल में 1 एवं 2 अप्रैल को कार्यालीन प्रक्रियाओं, अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेच्युटी, लेखा अभिलेख, सेवा पुस्तिका एवं अन्य सेवा संबंधी प्रावधानों पर आधारित दो दिवसीय सेमिनार का सफल आयोजन किया गया.

इस पहल का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गहन एवं व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना था. कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) भोपाल, संजय तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कार्यालीन प्रक्रियाओं में शुद्धता और समयबद्धता प्रशासनिक कार्यकुशलता की आधारशिला है. उन्होंने अधिकारियों से नियमों की स्पष्ट समझ विकसित करने पर जोर दिया.

सेमिनार में प्रदेश की विभिन्न पुलिस इकाइयों से आए प्रतिभागियों के साथ-साथ प्रशिक्षणरत 44वें उप पुलिस अधीक्षक बैच के अधिकारियों ने भाग लिया. विशेषज्ञों द्वारा आयोजित सत्रों में अवकाश प्रबंधन, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवा अभिलेखों के संधारण और वित्तीय दस्तावेजों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई.

समापन सत्र में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस विभाग की प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा.

प्रदेश में 4 मौसम सिस्टम सक्रिय

45 जिलों में आंधी-बारिश व ओलावृष्टि का अलर्ट

भोपाल, 04 मार्च. मध्य प्रदेश में इस समय मौसम ने अचानक करवट ले ली है. एक साथ चार अलग-अलग मौसम सिस्टम सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है.

मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति 7 अप्रैल तक बनी रह सकती है, जिससे लोगों और किसानों दोनों को सतर्क रहने की जरूरत है. दरअसल, प्रदेश में दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवाती परिसंचरण) और दो टर्फ लाइन सक्रिय हैं. एक टर्फ लाइन प्रदेश के बीचोंबीच गुजर रही है, जबकि दूसरी ऊपरी स्तर पर बनी हुई है. इसके साथ ही पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में चक्रवाती गतिविधियां भी जारी हैं. इन सभी सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार अस्थिर बना हुआ है और कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिर रहे हैं. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए लगभग 45 जिलों में अलर्ट जारी किया है. इनमें भोपाल, ग्वालियर समेत कई बड़े जिले शामिल हैं.

जबलपुर, कटनी, छतरपुर, पन्ना और दमोह में ओलावृष्टि की विशेष चेतावनी दी गई है. इसके अलावा प्रदेश के कई अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. हवा की रफ्तार भी काफी तेज रहने की आशंका है. कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आंधी चल सकती है, जबकि अन्य स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. इस कारण पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और फसलों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है. 7 अप्रैल के बाद एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होगा, जिससे 10 अप्रैल तक हल्की मौसम गतिविधियां जारी रह सकती हैं. इसके बाद जैसे ही मौसम साफ होगा, तापमान तेजी से बढ़ेगा.

दिशा लर्निंग सेंटर से युवाओं को सुरक्षा में मिली सफलता

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना एवं उप पुलिस महानिरीक्षक डॉ. विनीत कपूर के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में संचालित 'दिशा लर्निंग सेंटर' पहल युवाओं को नि:शुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शारीरिक प्रशिक्षण प्रदान कर उल्लेखनीय परिणाम दे रही है.

यह कार्यक्रम न केवल युवाओं के आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, बल्कि उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए भी प्रेरित कर रहा है. छिंदवाड़ा से इस पहल की एक महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है, जहां पुलिस लाइन में संचालित केंद्र ने विभिन्न सुरक्षा बलों की भर्ती में अभ्यर्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में मदद की है. कुल 17 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 11 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) में तथा 6 अभ्यर्थी एसएससी जीडी के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में चयनित हुए हैं.

डायल-112 कर्मियों की त्वरित कार्रवाई

घायल व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता कराई गई उपलब्ध

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. इंदौर जिले में डायल-112 कर्मियों की त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई से रात्रि गश्त के दौरान घायल अवस्था में मिले एक व्यक्ति को समय पर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई.

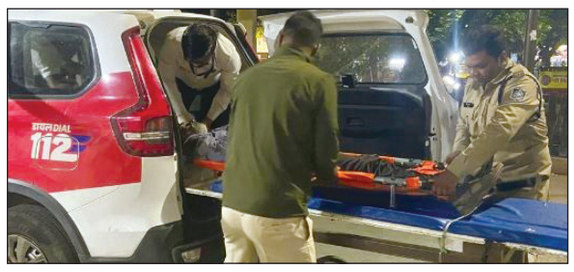

यह घटना 4 अप्रैल को थाना तेजाजी नगर क्षेत्र के अंतर्गत केलोद फाटा के पास हुई. नियमित गश्त के दौरान एफआरवी स्टाफ ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में देखा. इसकी सूचना तुरंत राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को दी गई, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई.

तत्परता दिखाते हुए आरक्षक मोहन मालवीय और आरक्षक आशीष पालीवाल तथा पायलट मोहित जाट ने घायल व्यक्ति को बिना किसी देरी के एफआरवी वाहन के माध्यम से एम.वाय. अस्पताल, इंदौर पहुंचाया. डायल-112 टीम की सतर्कता और मानवीय दृष्टिकोण के कारण घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सका.

यह घटना 'डायल-112 हीरोज' पहल के तहत मध्यप्रदेश पुलिस की आमजन की सुरक्षा, आपातकालीन सहायता और नागरिक सेवा के प्रति चौबीसों घंटे प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

आरपीएफ ने सुरक्षा और सहायता में रिकॉर्ड उपलब्धियां हासिल की

भोपाल, 4 अप्रैल. पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल मंडल के अनुसार, वित्तीय वर्ष अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान रेल सुरक्षा बल ने यात्रियों और रेल संपत्ति की सुरक्षा में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कीं.

आरपीएफ ने चौबीसों घंटे सतर्क रहकर सुरक्षित माल परिवहन के साथ-साथ यात्रियों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 720 बिछड़े, घर से भागे या अपहृत बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों या चाइल्ड लाइन को सौंपा गया. ऑपरेशन अमानत में 973 यात्रियों को लगभग 2.88 करोड़ मूल्य का खोया सामान वापस किया गया. ऑपरेशन जीवन रक्षा के अंतर्गत 33 लोगों की जान बचाई गई, जबकि ऑपरेशन मेरी सहेली के तहत प्रतिदिन औसतन 110 ट्रेनों में महिला यात्रियों को सहायता दी गई. रेल अधिनियम के तहत 53,566 मामलों में कार्रवाई कर ?3.81 करोड़ जुर्माना वसूला गया. ऑपरेशन उपलब्ध में 64 लोगों को गिरफ्तार कर 52 लाख से अधिक मूल्य के ई-टिकट जब्त किए गए. अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ 18,166 मामलों में कार्रवाई कर 2.20 करोड़ जुर्माना वसूला गया. रेल संपत्ति चोरी के 328 मामलों में 635 आरोपियों को गिरफ्तार कर संपत्ति बरामद की गई.

फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर संविदा अधिकारी बर्खास्त

सिवनी, 04 अप्रैल. जिले की जिला पंचायत में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए परियोजना अर्थशास्त्री (संविदा) वंदना मुड़िया की सेवाएं 16 वर्षों बाद समाप्त कर दी गई हैं.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजली शाह द्वारा की गई है. मामले में संबंधित के खिलाफ डूंडासिवनी थाना में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में पुलिस ने आवेदन वापस कर पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. यह मामला भोपाल स्थित लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज शिकायत के बाद उजागर हुआ. जांच में सामने आया कि संबंधित अधिकारी ने अपनी वास्तविक जाति छिपाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत नौकरी प्राप्त की, जबकि दस्तावेजों में उनकी जाति ढीमर (ओबीसी) दर्ज पाई गई.

नाम सुधार सूचना

मैं दीपा नामदेव W/o देवेन्द्र नामदेव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़ी निरपति सिंह, पो.आ. ढेरा थाना व तहसील मऊगंज जिला मऊगंज (म.प्र0)। मैं शादी के पूर्व भारतीय जीवन बीमा निगम रीवा क्र. 01 से पालिसी ली थी जिसका नं. 357155425 है। उक्त पालिसी में मेरा नाम दीपावली नामदेव दर्ज है जबकि हमारे सभी रिकार्ड आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक में दीपा नामदेव है। अतः सभी रिकार्ड के अनुसार मेरा नाम दीपावली नामदेव के स्थान पर दीपा नामदेव W/o देवेन्द्र नामदेव दर्ज किया जाये व पढ़ा जाय।

कार्यालय, नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्र./98/स्व.भा.मि./2026 सिंगरौली, दिनांक, 02.04.2026

सार्वजनिक सूचना

(निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट के उपयोग/बिक्री संबंधी)

नगर पालिक निगम सिंगरौली अंतर्गत समस्त आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम या सरकारी निर्माण गतिविधियों में निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट से बनी वस्तुओं (यदि उपलब्ध हो) के उपयोग बिक्री के लिए प्रावधान नियत करते हुए दरें तय की गई हैं:-

(1) पेवर ब्लॉक/फर्श के ब्लॉक 15.00 रूपये प्रति नग।
(2) संचरात्मक क्रांकीट-1000.00 रूपये प्रति ट्राली।
(3) ईंटें-1000.00 रूपये प्रति ट्राली ।
(4) निर्मित समुच्चय संबंधी 1000.00 रूपये प्रति ट्राली ।

नागरिकों हेतु निकाय द्वारा टोल फ्री नम्बर 7610107107 जारी किया गया है जिसके माध्यम से उक्त सुविधाओं का लाभलिया जा सकता है।

नोडल अधिकारी
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (2.0)
नगर पालिक निगम सिंगरौली

गंभीर आरोप | कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- किसानों के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा खतरे में है

एमपी खाद्यान्न उपार्जन प्रणाली में 'लूट' : पटवारी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 4 अप्रैल. जीतू पटवारी, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ने राज्य की खाद्यान्न उपार्जन, भंडारण और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और राजनीतिक संरक्षण के गंभीर आरोप लगाते हुए इसे 'संगठित लूट' करार दिया है, जो किसानों के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रही है.

उन्होंने दावा किया कि रायसेन जिले के वेयरहाउसों में लगभग 20,000 मीट्रिक टन

35 करोड़ से खरीदा गया था 20,000 मीट्रिक टन गेहूं

4 वर्षों में प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं सड़ चुका

गेहूं, जिसे 35 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा गया था, सड़ने के लिए छोड़ दिया गया. रखरखाव और कीटनाशक के नाम पर इसकी लागत 150 करोड़ रुपये तक पहुंचा दी गई. 34 बार छिड़काव के बावजूद अनाज के खराब हो जाने को उन्होंने फर्जी बिलिंग और अधिकारियों-ठेकेदारों की मिलीभगत का परिणाम बताया. पटवारी ने कहा कि यह समस्या व्यापक है.

पिछले चार वर्षों में प्रदेश में 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं सड़ चुका है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

जबलपुर और सिवनी में सामने आए 'घोस्ट ट्रांसपोर्ट' घोटाले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि 92 प्रतिशत ट्रिप फर्जी थीं, जिनमें स्कूटर जैसे वाहनों से भारी मात्रा में अनाज ढोने का दावा किया गया.

उन्होंने वेयरहाउस आवंटन में पक्षपात और भुगतान में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया. 26 प्रतिशत से अधिक बच्चों में कुपोषण का हवाला देते हुए उन्होंने स्थिति को गंभीर बताया. कांग्रेस ने मामले की फोरेंसिक जांच, आवंटन में पारदर्शिता, दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई, नुकसान की भरपाई और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सख्त गुणवत्ता नियंत्रण की मांग की है.

आम सूचना

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार कीर्ति वीर सिंह तोमर पुत्री स्व0 श्री विजय पाल सिंह तोमर निवासी कृष्णनगर सतना, जिला सतना म0प्र0 के है जिनके द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है कि संयुक्त परिवार की भूमि ग्राम कोटर तह0 कोटर जिला सतना में स्थित आराजी न0-121/2 रकवा-0.786 हे0 एवं आराजी न0-122 रकवा-0.797 हे0 कुल किता 02 कुल रकवा-1.766हे0 है जो संयुक्त परिवार की भूमि है उक्त आराजियो का प्रकरण वर्तमान समय में न्यायालय में विचाराधीन है तथा उक्त प्रकरण में जब तक किसी प्रकार का निराकरण नहीं होता है ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति उक्त आराजी का क्रय-विक्रय न करे यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा उक्त सूचना उपरांत उक्त आराजी का क्रय-विक्रय किया जाता है तो उक्त सौदा न्यायालय प्रक्रिया द्वारा विक्रय पत्र को निरस्त एवं शून्य कराया जावेगा।

अस्तु क्रय-विक्रय अनुबंध, गहननामा न करें अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगें।

स्थान-सतना, दिनांक- 4.4.2026

भवदीय
नारेन्द्र बहादुर सिंह
एडवोकेट
जिला न्यायालय सतना

कार्यालय, नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्र./100/ स्व. भा. मि./2026 सिंगरौली, दिनांक 02.04.2026

सार्वजनिक सूचना

(Notified Ban on Manual Hazardous Entry: Without Safety Gear)

नगर पालिक निगम सिंगरौली क्षेत्रान्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक संस्थानों में स्तिथ सेप्टिक टैंक से मल को मैला टैंकर द्वारा सुरक्षापूर्वक संग्रहित किया जाता है एवं इसका निपटान निकाय के फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट में किया जाता है। निकाय द्वारा सर पर मैला ढोने वाली प्रथा एवं बिना सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक स्थानों में मैन्युअल एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अत: आपको सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सर पर मैला ढोने का कार्य किया जाता है या किसी व्यक्ति द्वारा करवाया जाता है या बिना सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक स्थानों में मैन्युअल एंट्री पाई जाती है तो शत प्रतिशत कानूनी कार्यवाही सहित आर्थिक दंड अधिरोपित किये जाने का प्रावधान हैं। सेप्टिक टैंक की सफाई अनिवार्य रूप से प्रत्येक 3 वर्ष में करवाना सुनिश्चित करे और निकाय द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर 7610107107 पर संपर्क करें।

नोडल अधिकारी
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (2.0)
नगर पालिक निगम सिंगरौली